1992-93

1. Sikkim
2. Haryana
3. Tamil Nadu
4. Orissa
5. Arunachal Pradesh

1993-94 (to date)

1. Uttar Pradesh
2. Madhya Pradesh
3. Himachal Prdaseh
4. West Bengal
5. Lakshadweep

ESIC Scheme at Paradip Phosphates Ltd.

*370. SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY:

Will the Minister of Labour be pleased to state:

(a) whether Government are aware that E.S.I.C. component of contribution passed on to the contractors working under Paradip Phosphates Ltd. is a part of their agreement;

(b) if so, what was the total money passed on to the contractors by Paradip Phosphates Ltd. and since when;

(c) what has happened to this money in the absence of ESIC scheme at Paradip Phosphates Ltd.; and

(d) whether government propose to recover this money from contractors and pass on the same to the workers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

गरीबी रेखा के निर्धारण के संबंध में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

*371. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री धीरेन जे० शाह :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1989 में प्रो. डी. टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञा समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने गरीबी रेखा निर्धारित करने संबंधी अपने मत से संबंधित अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था ;

(ग) क्या यह सच है कि समिति ने इस बात को स्वीकार किया है कि वर्ष 1987-88 के दौरान देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या 30 प्रतिशत की बजाय 38 प्रतिशत थी, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की मान्य संख्या के अनुरूप नहीं है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि समिति ने गरीबी रेखा निर्धारित करने हेतु नई परिभाषा स्वीकार करने का आग्रह किया है ;

(ङ) यदि हां, तो प्रस्तावित नई परिभाषा क्या है और इस परिभाषा को स्वीकार किये जाने के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, ;

(च) समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन को बदेनजर रखते हुए क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में कतिपय संशोधन की आवश्यकता महसूस की है ; और

(छ) यदि नहीं, तो क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में सभी लोगों के लिए प्रतिदिन, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरीज के उपयोग की व्यवस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा सितम्बर, 1989 में प्रोफेसर डी. टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में गरीबों के अनुपात तथा संख्या के आकलन पर गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट 24 जुलाई, 1993 को उपाध्यक्ष, योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ।

(ग) से (च) विशेषज्ञ दल ने खपत व्यय, कीमत परिवर्तनों राज्यों में कीमत विभिन्नताओं तथा गरीबों के खपत पैटर्न से संबंधित आंकड़ों के विस्तृत अध्ययन के उपरांत गरीबी आकलन के लिए एक संशोधित कार्यप्रणाली की सिफारिश की है, विशेषज्ञ दल ने गरीबी को रहन-सहन के स्तर तथा रोजगार एवं सरकार द्वारा प्रदान की गई निःशुल्क सामाजिक सेवाओं से जोड़ते हुए एक गहन अध्ययन का भी सुझाव दिया है । सिफारिशों के निहितार्थों का अध्ययन किया जा रहा है ।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबों के उत्थान को उच्च प्राथमिकता दी गई है ।

ISI marked products in the country

*372. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that I.S.I. marked products have not come up to the prescribed standards in each market in the country;

(b) if so, the number of such items deducted from standard-Mark during the years 1991, 1992 and so far in 1993;

(c) whether any specific items have been identified by Government in this context to be covered under I.S.I. Mark; and

(d) if so the details thereof?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): (a) No such reports have come to the notice of the Bureau of Indian Standards (BIS). BIS takes a number of steps to ensure that ISI-marked products conform to prescribed standards through surveillance mechanism which includes periodic surprise inspections of the manufacturing premises of the licensees, testing of samples drawn from the factories of the licensees and open market, action against the licensees as also against those making unauthorised use of ISI Mark, investigation of complaints from consumers and feedback from organised consumers.

(b) In case of failure on the part of manufacturers to meet the prescribed standards, standard mark i.e. ISI is cancelled, thereby prohibiting the manufacturers from using the Standard Mark. The number of licences cancelled during the relevant years is as follows:

1991-92	1992-93	1993-94
61	15	15 Till 25-6-93

(c) BIS Certification Marking Scheme is voluntary in nature. However, in certain cases, Government has made it mandatory on considerations of safety, health and consumer production.

(d) The list of 129 standards in respect of which BIS Mark has been made compulsory is given in the enclosed statement.